



KEDIA
सेजस्थान
KOTHI & WALK-UP APARTMENT
अजमेर रोड, जयपुर

www.rera.rajasthan.gov.in
RERA No. RAJ/P/2023/2387



आज रात से 5 लाख रेट बढ़ेगी !

“मंडी” जैसे दाम
लकजरी
आपके नाम



लकजरी की कीमत : ₹4200/- में फ्लैट ! | ₹5400/- में कोठी !

PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	PRESENT RATE	31 JULY 2026	31 AUG. 2026	30 SEPT. 2026	31 OCT. 2026	30 NOV. 2026	30 DEC. 2026
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	68 Lacs	70 Lacs	72 Lacs	74 Lacs	76 Lacs	78 Lacs	80 Lacs
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	78 Lacs	80 Lacs	82 Lacs	84 Lacs	86 Lacs	88 Lacs	90 Lacs
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	85 Lacs	87.5 Lacs	90 Lacs	92.5 Lacs	95 Lacs	97.5 Lacs	1 Cr
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.10 Cr	1.125 Cr	1.15 Cr	1.175 Cr	1.20 Cr	1.225 Cr	1.25 Cr
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.32 Cr	1.35 Cr	1.38 Cr	1.41 Cr	1.44 Cr	1.47 Cr	1.50 Cr
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.70 Cr	1.75 Cr	1.80 Cr	1.85 Cr	1.90 Cr	1.95 Cr	2 Cr

FIXED PRICE

NO MIDDLE MEN

KEDIA®

1800-120-2323

info@kedia.com
www.kedia.com
78770-72737



SCAN QR FOR
• LOCATION
• ROUTE MAP
• SITE 360 TOUR
• E-BROCHURE
• WALKTHROUGH

KEDIA™
Pavitra



पहले सरसों के तेल की झाँझ से आँखों में आँसू आ जाते थे... अब क्यों नहीं? आखिर बदला क्या है... सरसों का तेल या हमारी नाक ?

नानी-दादी के ज़माने की वही 0.36 की तेज़ प्राकृतिक झाँझ अब केडिया पवित्र कच्ची घानी सरसों के तेल में !

कोल्ड प्रेस

पहली धार से निर्मित
उच्च गुणवत्ता वाला
कच्ची घानी तेल

तेज झाँझ
(0.36 झाँझ)

कच्ची घानी सरसों तेल

MRP ₹4000.00
15 ltr

MRP ₹300.00
1 ltr

द्विपल फ़िल्टर्ड मूंगफली तेल

MRP ₹4000.00
15 ltr

MRP ₹300.00
1 ltr

द्विपल फ़िल्टर्ड

सोर्टेक्स क्लीन
मूंगफली दानों
से निर्मित

Low FFA
(0.50 से कम)

प्रोडक्ट्स कैटेगरी

आटा | गेहूँ | दाल | चावल | खड़े, पीसे एवं ब्लेंडेड मसाले | ड्राई फ्रूट्स | कुकिंग ऑयल | चाय | पोहा | मिश्री | गुड | हींग | मसाला सत्तू | सेंधा नमक सहित कम्प्लीट किचन बाल्केट

कॉल लगाओ, गाड़ी बुलाओ

1800 120 2727

अपने नजदीकी रिटेलर और
Zepto पर उपलब्ध !



T&C Apply
MRP ₹ Incl. of all taxes

एक तरफ प्रधानमंत्री और सरकार की प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने की कोशिश की सोच है

दूसरी ओर भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ नेता, जिनमें यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन भी शामिल हैं, आंदोलनरत छात्रों को गैरसंस्कारी बता रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े भदे शब्दों में परिभाषित कर रहे हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अब भाजपा और आरएसएस के उन नेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे जेन ज़ेड प्रदर्शनकारियों के आचरण और भाषा की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों का आचरण "भारतीय मूल्यों के अनुरूप नहीं था और इससे समाज को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।"

इससे पहले केरल के हिंदुत्व विचारक टी. जी. मोहनदास और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत सहित, कई नेताओं ने भी छात्र प्रदर्शनकारियों की आलोचना की थी। उनका कहना था कि प्रदर्शन के दौरान अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसका बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने आज कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा ने "पूरे समाज का सिर शर्म

- यह दुविधा सोची समझी रणनीति है या विचारों में वाकई में मतभेद होने का संकेत है।
- अगर इस दुविधा का हल नहीं ढूंढा गया तो आंदोलन और उग्र हो सकता है और उसके परिणाम सभी के लिए दुखदायी हो सकते हैं।

से शुका दिया।" उन्होंने कहा, "जो कुछ भी कहा गया, वह हमारी संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नहीं था।" राज्यपाल ने कहा कि बेटियों को वेद, उपनिषद, भगवद्गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि उनमें अच्छे संस्कार और नैतिक चरित्र का विकास हो।

विर्डबना यह है कि ये टिप्पणियां प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत और सामंजस्य बनाने की केन्द्र सरकार की नीति से अलग दिखाई देती हैं। यह अंतर साफ नजर आता है। एक ओर केन्द्र सरकार ने व्यवहारिक रुख अपनाते हुए, बातचीत, समझौते और अंततः आंदोलन की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई, जो संवाद और

तनाव कम करने की संस्थागत सोच को दर्शाता है। दूसरी ओर, भाजपा और आरएसएस से जुड़े कुछ नेताओं ने टकरावपूर्ण, नैतिक उपदेश देने वाला और कई बार हिंसा का समर्थन करने तथा हिंसा को जरूरी समझने वाला रुख अपनाया। उन्होंने युवा प्रदर्शनकारियों को सामाजिक रूप से पतित बताया तथा उनके खिलाफ घातक बल प्रयोग की बात कही। यह अंतर दिखाता है कि जहां सरकार आधिकारिक स्तर पर संतुलित राजनीतिक प्रबंधन की नीति अपना सकती है, वहीं उसके वैचारिक समूहों के कुछ लोग असहमति के खिलाफ सांस्कृतिक और ध्ववीकरण वाली भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

की सीमाओं और युवाओं के असंतोष से निपटने के तरीके को लेकर कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं।

सबसे तीखा हमला केरल के हिंदुत्व विचारक और आरएसएस से जुड़े भाजपा के पूर्व बौद्धिक प्रकोष्ठ प्रमुख टी. जी. मोहनदास की ओर से आया। 26 जुलाई के आसपास जारी किए गए अपने यूट्यूब वीडियो में उन्होंने कहा कि यदि वे प्रभारी तथा अधिकृत होते तो जंतर-मंतर के चारों ओर चार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा देते, प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए तीन बार चेतावनी देते और उसके बाद पुलिस को गोली चलाने का आदेश देते। उन्होंने कहा, "कुछ लोग मर सकते हैं, कुछ लोग हमेशा के लिए दिव्यांग हो सकते हैं (लेकिन) चार घंटे के भीतर स्थिति पूरी तरह शांत हो जाएगी।" उन्होंने यह भी दावा किया कि "वामपंथी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और बहुजन" प्रदर्शनकारियों में शामिल महिलाएं "बलात्कार पसंद करती हैं" और (इसलिये) सामूहिक बलात्कार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली सरकार जंतर मंतर पर पैलेट गन से घायलों का इलाज कराये

नई दिल्ली, 30 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह जंतर-मंतर के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों का इलाज कराए। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के असलहों के मूवमेंट को संरक्षित रखने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि किसी

- सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड एक्शन फोर्स के असलहों के मूवमेंट को संरक्षित रखने का भी आदेश दिया।

विशेष घटना में पैलेट गन के इस्तेमाल की वैधता की जांच की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश आईबी के पूर्व निदेशक और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद और दो अन्य पीड़ितों की याचिका पर दिया है। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कर्नाट प्लेस के पास भारी भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए तैनात आरएएफ ने पहले आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। उसके बाद पैलेट से लैस पंप एक्शन गन का इस्तेमाल किया गया।

याचिका में कहा गया है कि बल प्रयोग करने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई और कई प्रदर्शनकारियों की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐसा लगता है, ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ बहादुरी से संघर्ष कर रहा है

क्या अब ईरान के पास उन गिने-चुने, अलग-थलग पड़े आतंकी गुटों का ही समर्थन रह गया है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों और बलों पर अचानक हमला किया, जो भी उस दिन, जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाइट हाउस में ट्रंप से मिले थे। यह बैठक लंबे अंतराल के बाद हुई थी, जब दोनों नेताओं के संबंधों में आई खटास कुछ कम होने का संकेत था और अमेरिका ने इजरायल को ईरान के ठिकानों पर नए हमले करने से रोका था।

जॉर्डन में अमेरिकी बलों पर ईरान के अचानक हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, जिन्हें उसने "भारी हमले" बताया। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं, जिनमें ईरानी नागरिक भी शामिल हैं। ईरान के क्रेसर तेल द्वीप पर अमेरिकी हमले में एक बच्चे सहित, तीन सदस्यों वाले पूरे परिवार की मौत हो गई।

कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि ईरान की आशंका है कि इजरायल एक बार फिर सक्रिय होकर उसके खिलाफ नया मोर्चा खोल सकता है। लेकिन इससे भी अधिक तात्कालिक कारण अमेरिका और

- अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने मध्यपूर्व में अमेरिका के सैन्य अड्डों व सैन्य बलों पर अचानक भारी हमले किए. हमले के लिए उसने वही दिन चुना, जिस दिन लंबे अरसे बाद वाइट हाउस में ट्रंप व इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी।

- अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान की व्यग्रता का कारण ओमान के तट से होकर होर्मुज़ का वैकल्पिक रास्ता खोलना है. क्योंकि अगर होर्मुज़ का विकल्प सफल हो गया तो ईरान से उसका "ट्रंप कार्ड" छिन जाएगा।

- होर्मुज़ पर नियंत्रण ईरान के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है और उसे इसमें स्थायी आय स्रोत भी दिख रहा है। ईरान किसी भी कीमत पर होर्मुज़ को नहीं छोड़ेगा, साथ ही वह नहीं चाहता कि इसका विकल्प बने। हालांकि, सारा विश्व चाहता है कि होर्मुज़ को ईरान की पकड़ से बाहर निकाला जाए।

ओमान की वह संयुक्त पहल थी, जिसके तहत होर्मुज़ स्ट्रेट में ओमान के तट से सटे और ईरान द्वारा नियंत्रित आधिकारिक मार्ग के दक्षिण में एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही थी। यदि यह व्यवस्था स्थिर हो जाती, तो इससे ईरान

के सबसे बड़े रणनीतिक हथियार, होर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण व्यावहारिक रूप से समाप्त हो जाता। दरअसल, ईरान के उप-विदेश मंत्री ने हाल ही में दिए गए एक साक्षात्कार में इस चिंता को स्पष्ट रूप से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुंबई की एयर इंडिया बिल्डिंग बनी महाराष्ट्र का नया सीएम ऑफिस

23 मंजिला इस सी फेसिंग इमारत को गत माह 1601 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार ने खरीदा है

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। समुद्र के किनारे बनी 23 मंजिला मशहूर एयर इंडिया बिल्डिंग, जिसे पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने 1601 करोड़ रुपये में खरीदा था, अब मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का नया कार्यालय बनेगी। यह कार्यालय राज्य सचिवालय "मंत्रालय" से अलग जगह होगा।

महाराष्ट्र सरकार को मंत्रालय के पास दक्षिण मुंबई के प्रमुख इलाकों में ऑफिस की जगह की कमी का सामना

मध्य प्रदेश पुलिस के तत्कालीन एआईजी को दुष्कर्म के मामले में उग्र कैद

जयपुर, 30 जुलाई। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने आपराधिक मामले में महिला के पति की मदद के नाम पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के तत्कालीन एआईजी अनिल मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, पीड़िता की नाबालिग पुत्री से

- अदालत ने एआईजी अनिल मिश्रा को पीड़िता की नाबालिग पुत्री से अश्लीलता के मामले में 3 साल की सजा भी सुनाई।

अश्लीलता करने के मामले में भी मिश्रा को तीन साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप वाजपेयी और पीड़ित पक्ष के वकील मुकेश पाठक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 11 जुलाई, 2014 को महिला थाना दक्षिण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसके पति के खिलाफ फरवरी, 2012 में एमपी के सिरोंहा में शिकायत दर्ज हुई थी। इस दौरान उसके पति ने उसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अब मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस "मंत्रालय" (महाराष्ट्र का राज्य सचिवालय) से अलग अपना ऑफिस चलाएंगे, बाद में अन्य विभागों को भी यहाँ शिफ्ट किया जाएगा।
- एयर इंडिया बिल्डिंग 1974 में बनी थी। एयर इंडिया के निजीकरण और टाटा समूह द्वारा इसके अधिग्रहण के बाद इस बिल्डिंग सहित एयर इंडिया की गैर प्रमुख परिसंपत्तियों का स्वामित्व एयर इंडिया एसैट्स होल्डिंग लिमिटेड को सौंप दिया गया था।

करना पड़ रहा था। एयर इंडिया बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 1974 में राज्य सरकार की रिकलेम की गई जमीन पर किया गया था। शुरुआती दिनों में इसकी लिफ्टों में सफर करने का अनुभव लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र हुआ करता था। एयर इंडिया के निजीकरण और टाटा समूह द्वारा उसके अधिग्रहण के बाद, इस इमारत सहित, उसकी सामान्य

(नॉन-कोर) संपत्तियां, एयर इंडिया एसैट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल) को सौंप दी गई थी। फडणवीस के कार्यालय के अलावा, मंत्रालय के बाहर काम कर रहे सभी सरकारी विभागों को भी इस इमारत में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे सरकार को हर साल किराये के रूप में जाने वाले लगभग 200 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

आठ जिलों में स्थाई लोक अदालतों का गठन होगा

जयपुर, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 8 जिलों में स्थाई लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया है।

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार फलीदौ, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने फलीदौ, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूम्बर में लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया।

तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ एवं सलूम्बर में स्थाई लोक अदालत खोली जाएंगी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिना निर्वाचित हुए छः माह से अधिक समय तक मंत्री बने रहने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बिहार सरकार को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जुलाई। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एक अजीब तरह की जांच का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि वे विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन के सदस्य बने बिना मंत्री पद पर बने हुए हैं।

दीपक प्रकाश पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र हैं। उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, भाजपा की सहयोगी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को यह बताना होगा कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने बिना छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर कैसे बने रहे।

- यह मामला पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का है, वे ना तो विधानसभा के सदस्य हैं, ना ही विधान परिषद के, इसलिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज हुई है।

- दीपक प्रकाश पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र हैं, जिनकी पार्टी आरएलएम एनडीए की घटक है।

- दीपक प्रकाश के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट राकेश कुमार सिंह ने याचिका दायर की है, जिसमें दीपक प्रकाश को बिहार की नई सरकार में मंत्री बनाए जाने को चुनौती दी गई है।

- इससे पहले उन्हें 20 नवम्बर 2025 को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था, वे तब निर्वाचित नहीं थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता के

वकील ने कहा कि छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी दीपक प्रकाश बिहार विधानसभा या विधान

परिषद के लिए निर्वाचित हुए बिना मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए कहा, "माई लॉर्ड, अब छह महीने से अधिक हो चुके हैं और वे अब भी मंत्री हैं।"

बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि मामला पहले से ही 27 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। उन्होंने सुनवाई की तारीख पहले करने का निर्णय अदालत के विवेक पर छोड़ दिया। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह पूरी तरह कानून का प्रश्न है और राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि संविधान के किस प्रावधान के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को, जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, छह महीने से अधिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान विधानसभा का सत्र 20 अगस्त से

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान की सोलहवीं विधानसभा का छठा सत्र आगामी 20 अगस्त से शुरू होगा। इस संबंध में राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल

- राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अधिसूचना जारी की।

हरिभाऊ बागडे ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त को प्रातः 11 बजे राजस्थान विधानसभा भवन, ज्योति नगर, जयपुर में आहूत किया है। विधानसभा के इस सत्र में सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों एवं अन्य सरकारी कार्यों को सदन में प्रस्तुत कर सकती है। इसके साथ ही, विपक्ष भी प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजलदेसर में मूसलाधार बरसात से सरकारी अस्पताल में पांच फीट पानी भरा

तेज बारिश से पूरे कस्बे में जलभराव की स्थिति बन गई, कई घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया

राजलदेसर, (निसं)। राजलदेसर में गुरुवार सुबह छह बजे से सात बजे के बीच हुई एक घंटे से अधिक की मूसलाधार बारिश ने कस्बे की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। तेज बारिश के चलते पूरे कस्बे में जलभराव की स्थिति बन गई और कई मुख्य मार्गों सहित निचले इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया।

पानी भरने से लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा तथा कई घरों और दुकानों में भी पानी घुस जाने से घरेलू सामान व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा। बारिश के कारण गांधी चौक, रेलवे स्टेशन रोड, फ्रेंड्स सोसायटी मार्ग, महेंद्र मुनि मार्ग, मेहंदीपुर बालाजी मार्ग, मुरलाई बस्ती, अंजनी माता मंदिर मार्ग, ढोली बस्ती, वार्ड संख्या 26 और वार्ड संख्या 35 सहित कई क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया। कई स्थानों पर सड़कें तालाब जैसी नजर आईं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक प्रभावित राजकीय चिकित्सालय रहा, जहां 4 से 5 फीट तक पानी भर जाने से रोगी भर्ती वार्ड, नर्सिंग क्वार्टर, एक्स-रे कक्ष, प्रयोगशाला, लेबर रूम तथा



राजलदेसर में हुई बारिश से चिकित्सालय में पानी भरने से लोगों को परेशानी की सामना करना पड़ा।

स्टोर रूम में पानी घुस गया। इससे अस्पताल के उपकरण, दवाइयों और अन्य सामग्री को लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मरीजों और चिकित्सकर्मियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान नगर पालिका की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हुए। सुबह करीब 5:30 बजे बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद पंप हाउस

में लगे जनरेटर में डीजल उपलब्ध नहीं होने से जल निकासी का कार्य समय पर शुरू नहीं हो सका, जिसके कारण कई इलाकों में पानी लंबे समय तक जमा रहा। हालांकि अच्छी बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने इसे खरीफ फसलों के लिए लाभदायक बताया। साथ ही

लगातार पड़ रही उमस और गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। अधिशासी अधिकारी सीताराम मीणा ने बताया कि जलभराव की स्थिति को देखते हुए नगर पालिका के सभी कर्मचारियों को राहत कार्य में लगाया गया है। जिन क्षेत्रों में घरों में पानी घुस गया है, वहां टैंकर और पंपसेट लगाकर पानी निकासी का कार्य कराया जा रहा है। मुख्य

चूरू में छह जुआरी गिरफ्तार

चूरू, (कासं)। पुलिस थाना रतननगर की टीम ने जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 19,900 रुपए जुआ राशि जब्त की है। थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर सुभाषचन्द्र के नेतृत्व में टीम ने गश्त के दौरान एनएच 52 सड़क किनारे रोही रतननगर से आरोपी उमर कुरैशी पुत्र जाफर व्यापारी निवासी वार्ड नं. 24 रामगढ़ जिला सीकर, मोहम्मद हारुन पुत्र याकूब व्यापारी निवासी वार्ड नं. 30 रामगढ़ जिला सीकर, मोहम्मद रनजान पुत्र मोहम्मद सलीम तेली निवासी वार्ड नं. 20 रामगढ़ जिला सीकर, लतीफ कुरैशी पुत्र अब्दुल रहमान भिंशरी निवासी वार्ड नं. 30 रामगढ़ जिला सीकर, इलियास पुत्र गुलामनवी व्यापारी वार्ड नं. 30 रामगढ़ पुलिस थाना रामगढ़ जिला सीकर और सलीम पुत्र मोहम्मद यासीन व्यापारी निवासी वार्ड नम्बर 30 रामगढ़ के कब्जे से जुआ राशि जप्त कर प्रकरण दर्ज किया।

लाखों की अवैध शराब जब्त

बीकानेर, (निसं)। आबकारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 180 कार्टन अंग्रेजी शराब से भरी पिकअप जब्त की। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जिससे पूछताछ जारी है। शराब की बाजार कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है।

जिला आबकारी अधिकारी मनोज बिस्पा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में हाईवे पर टीम मुखबिर की सूचना पर अलर्ट रही। जैसे ही संदिग्ध पिकअप आई तो उसे रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान पिकअप में चड़्गौढ़ ब्रांड की 180 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली। ऐसे में पिकअप और शराब को जब्त किया। मामले में बीकानेर के सोडबाली (लुणकसर) निवासी 40 वर्षीय गिरधारीसिंह पुत्र अमरसिंह को गिरफ्तार किया।

महिला सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है : राज्यपाल बागड़े

कोटा, (निसं)। कृषि विश्वविद्यालय कोटा एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित द्वि दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला स्वस्थ एवं शिक्षित महिला सशक्त राष्ट्र का शुभारम्भ गुरुवार को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लीकल्वर मैनेजमेंट कोटा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। कार्यक्रम में देशभर से लगभग 300 वैज्ञानिकों, शिक्षकों, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया।

मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राष्ट्र निर्माण का आधार केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि बौद्धिक विकास, ईमानदारी, जिज्ञासा तथा सतत अध्ययन की प्रवृति है। उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर अध्ययन करने, प्रश्न पूछने और भारतीय ज्ञान परंपरा एवं वैदिक शिक्षा के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है तथा शिक्षित एवं स्वस्थ महिलाएँ ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है।



कोटा में राज्यपाल बागड़े ने राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी ने कहा कि गरीब एवं वंचित बालिकाओं की शिक्षा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित एवं पोषित आहार के माध्यम

से रोग प्रबंधन पर विशेष बल देते हुए कहा कि उचित भोजन अनेक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण का प्रभावी माध्यम बन सकता है। उन्होंने शिक्षा, संस्कार एवं स्वास्थ्य को राष्ट्र की उन्नति के तीन प्रमुख स्तंभ बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि

- स्वस्थ एवं शिक्षित महिला : सशक्त राष्ट्र राष्ट्रीय कार्यशाला का कोटा में शुभारम्भ हुआ

विश्वविद्यालय, कोटा की कुलपति डॉ. विमला डूकवाल ने कहा कि नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सहभागिता को समावेशी विकास का आधार बताते हुए प्रत्येक बालिका एवं महिला तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा कार्यशाला की शोध पत्र स्मारिका का विमोचन भी किया गया। कार्यशाला के प्रथम तकनीकी सत्र आहार, विहार और महिला में डॉ. नीलांबरी दवे एवं डॉ. मिताबेन राजेश कोटेचा ने महिलाओं के स्वास्थ्य, संतुलित आहार, जीवनशैली,

भारतीय परंपरागत भोजन एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विस्तार से प्रकाश डाला। द्वितीय तकनीकी सत्र महिला एवं मानसिक स्वास्थ्य में डॉ. अजीत शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन तथा बदलती जीवनशैली के प्रभावों पर विस्तृत व्याख्यान दिया।तृतीय तकनीकी सत्र महिला शारीरिक स्वास्थ्य जागरूकता में डॉ. ज्योति शर्मा, डॉ. अनुपमा चतुर्वेदी एवं डॉ. अंजना शर्मा ने महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य, स्त्री रोगों की रोकथाम, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, स्वच्छता एवं समय पर चिकित्सकीय परामर्श के महत्व पर विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। कार्यक्रम के दौरान महिला स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं सशक्तिकरण विषयक पोस्टर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन राज्यपाल एवं विशिष्ट अतिथियों ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों के नवाचारों एवं वैज्ञानिक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए शोध को समाजोपयोगी बनाने का आह्वान किया।

अलवर में बैंक जा रहे छात्र पर हमला, अपहरण की भी कोशिश

अलवर, (निसं)। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के खुदनपुरी इलाके में गुरुवार सुबह एक पॉलिटेक्निक छात्र पर दिनदहाड़े हमला करने का मामला सामने आया है। छात्र का आरोप है कि थार और कई मोटरसाइकिलों पर आए बदमाशों ने पहले उसकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिराकर बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, रिवाल्वर दिखाकर जबरन गाड़ी में बैठाने की भी कोशिश की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

घायल छात्र रितिक वर्मा (21) के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे अपनी स्कूटी से दिल्ली रोड स्थित एसबीआई बैंक में 1.50 लाख रुपए जमा कराने जा रहा था। जैसे ही वह चक्रधारी मंदिर के पास पहुंचा, पीछे से आई एक थार और मोटरसाइकिलों पर सवार युवकों ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके बाद सभी ने उसे धर लिया और सड़क

- घटना का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
- थार और मोटरसाइकिलों पर सवार युवकों ने छात्र की स्कूटी को टक्कर मारकर मारपीट की

पर पटककर मारपीट शुरू कर दी। रितिक का आरोप है कि बदमाशों ने उसके सिर पर रिवाल्वर की बट से वार किया और लाठी-सरियों से हमला किया। इस दौरान उसे थार से कुचलने की कोशिश भी की गई। आरोपियों ने जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन शोर सुनकर आसपास लोग जमा हो गए। इसी मोटरसाइकिलों पर सवार युवकों ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इसके बाद सभी ने उसे धर लिया और सड़क

चंगुल से छुड़ाया गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी उसके पास मौजूद 1.50 लाख रुपए नकद और करीब 15 ग्राम वजनी चांदी की चेन छीनकर फरार हो गए। हमले में उसका आईफोन-15 भी टूट गया और स्कूटी को भी नुकसान पहुंचा। घायल छात्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रितिक ने पुलिस को दी शिकायत में अमित, विशाल, मन्नु, दिनेश, यश, सुमित, भूपेंद्र उर्फ भूपी, चंद्रप्रकाश उर्फ चौकू समेत अन्य युवकों को नामजद किया है। उसने बताया कि आरोपियों से उसकी पुरानी रंजिश चल रही है। उसके अनुसार 28 जुलाई को भी उसे मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई थी। अलवर पुलिस के अनुसार मारपीट और लूट की शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है। घटना का वीडियो भी खंगाला जा रहा है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जीके (ग्रुप-सी) एवं साइंस व संस्कृत की मॉडल उत्तरकुंजी जारी

अजमेर, (निसं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 अंतर्गत जीके (ग्रुप – सी) एवं साइंस तथा संस्कृत विषय की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 1 से 3 अगस्त 2026 तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उक्त परीक्षा के मॉडल

प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रूपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रूपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है।

छबड़ा के किसानों से कृषि कारोबार के नाम पर 12.50 लाख की ठगी

फर्जी फर्म बनाकर किसानों को शिकार बनाया, पंजाब से आरोपी को गिरफ्तार किया

छबड़ा, (निसं)। किसानों को कृषि व्यवसाय के नाम पर लाखों रुपये की चपत लगाने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह का छबड़ा पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी और उसके साथियों ने फर्जी फर्म बनाकर किसानों को फलदार बगीचा, पॉलीहाउस एवं जैविक खाद की एजेंसी दिलाने का झांसा दिया और करीब 12.50 लाख रुपये की ठगी कर फरार हो गए। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।

सीआई राजेश खटाना ने बताया कि 11 अक्टूबर 2023 को रिछड़ी श्यामपुरा निवासी छीतरलाल, देहरी निवासी नृपेश मीणा, इंद्रा कॉलोनी छबड़ा निवासी राधेश्याम मीणा तथा ग्रीन पार्क निवासी ओमप्रकाश ने छबड़ा थाने में मामला दर्ज कराया था। परिवार

- आरोपी और उसके साथियों ने फर्जी फर्म बनाकर किसानों को फलदार बगीचा, पॉलीहाउस एवं जैविक खाद की एजेंसी दिलाने का झांसा दिया
- किसानों से नकद और चेक से लाखों रुपये वसूल कर आरोपी फरार

स्थित एक बैंक में खाता खुलवाया और किसानों को खेतों में फलदार पौधों का बगीचा विकसित कराने, पॉलीहाउस स्थापित कराने तथा जैविक खाद की एजेंसी दिलाने का भरोसा दिया। आरोपियों ने किसानों से नकद और चेक के माध्यम से करीब 12.50 लाख रुपये वसूल किए और बाद में फरार हो गए। जांच के दौरान एफआईआर में दर्ज नाम, पते और मोबाइल नंबर भी फर्जी पाए गए। तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन के आधार पर पुलिस ने गिरोह से जुड़े रघुनाथ गुप्ता निवासी बनकसही, थाना मुंदेरावा, जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी लुधियाना (पंजाब) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और ठगी के अन्य मामलों की जांच की जा रही है।

नाबालिग किशोरी ने आत्महत्या की

डुंगरपुर, (निसं)। जिले के सदर थाना क्षेत्र के रोहनवाड़ा गांव में एक 16 वर्षीय किशोरी ने अपने घर के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने

- आत्महत्या करने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सदर थाना के एएसआई ने बताया कि रोहनवाड़ा निवासी टीना ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। टीना के अनुसार वह खेल पर काम करने गई हुई थी, जबकि उसकी 16 वर्षीय बेटी खुशबू घर पर अकेली थी। खेल से लौटने के बाद जब टीना ने बेटी को आवाज दी और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर खुशबू कमरे में पंखे से फंदे पर लटकती हुई मिली। घटना की सूचना मिलते ही पड़ोसी और पुलिस मौके पर पहुंचे। दरवाजा खोलकर किशोरी को नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और मामला दर्ज कर विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है।

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड, बीकानेर**

क्रमांक-अउ/वि. खण्ड/बी / निविदा/2026-27/666

दिनांक -27.07.2026

**ई-निविदा सूचना संख्या 21/वर्ष 2026-27
(NIB Code No PWD2627A1799)**

निम्न हस्ताक्षर कार्ा द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विद्युतीकरण कार्यों के लिए मोहम्मद निविदादा सा. नि. वि. , राज में सज्जम श्रेणी में पंजीकृत संवेद्यकों से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रणाली की प्रति अयोध्यास्तारकर्ता के कार्यालय में निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की दिनांक 27.07.2026 से 07.08.2026 तक सायं 6.00 बजे तक जमा कराई जा सकती है। तकनीकी निविदा दिनांक 10.08.2026 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। प्री-बिड मीटिंग की दिनांक 04.08.2026 दोपहर 01.00 बजे है। निविदा की अन्य शर्तें एवं स्वीकृत तकनीकी आदि का विवरण किसी भी कार्य दिवस के दौरान इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है। अन्य शर्तें व विवरण इस कार्यालय में व डीपीआर की वेबसाइट www.dipronline.org <http://sppp.raaj.nic.in> पर देखा जा सकता है। कुल कार्यों की संख्या 05 कुल लागत 56.45 लाख

UBN No.-1. PWD2627WSOB07636, 2. PWD2627WSOB07637, 3. PWD2627WSOB07639 4. PWD2627WSOB07640, 5. PWD2627WSOB07641

(पीयूष सिंह)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा. नि. वि. विद्युत खण्ड, बीकानेर

DIPR/C/13256/2026

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER
WATERSHED DEVELOPMENT AND SOIL CONSERVATION JODHPUR
(Near RTO Office, BJS Colony Jodhpur-342066)
E-mail: acewdscc.jodhpur@rajasthan.gov.in

S.No.F/ (JACE)-Ju-WDSC/MJA2.2/Bids/2026-27/

Date:

**NOTICE INVITING BID
NIB No. – JODHPUR/DIPR/PHA/01/2026-27**

Bids for Execution of following Watershed Development Works under MJA 2.2 Scheme of estimated cost as mentioned below are invited from interested bidders up to 14.08.2026, 05.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://eproc.raajasthan.gov.in> or <https://sppp.raajasthan.gov.in>) of the state, and www.watershed.raajasthan.gov.in in departmental website.

Bid No.	Block	Name of Work	Estimated Cost, Rs.in lakhs.	UBN No.
MJA-2.2/PHA/BAP/01	Bap	Construction of various Water harvesting structures under MJA 2.2 in Block-Bap, District Phalodi.	341.00	WSC2627WSOB01196
MJA-2.2/PHA/AJU/02	Aau	Construction of various Water harvesting structures under MJA 2.2 in Block-Aau, District Phalodi.	309.66	WSC2627WSOB01197
MJA-2.2/PHA/DECHJ/03	Dachu	Construction of various Water harvesting structures under MJA 2.2 in Block-Dachu, District Phalodi.	301.70	WSC2627WSOB01198
MJA-2.2/PHA/GHANTY/04	Ghantiyal	Construction of various Water harvesting structures under MJA 2.2 in Block-Ghantiyal, District Phalodi.	449.15	WSC2627WSOB01199
MJA-2.2/PHA/LCHAWAT/05	Lohawat	Construction of various Water harvesting structures under MJA 2.2 in Block-Lohawat, District Phalodi.	379.00	WSC2627WSOB01200

(Bhagrathi Bishnoi)
Additional Chief Engineer
Watershed Development & Soil Conservation
Jodhpur

DIPR/C/13204/2026

मंदिर और सूने मकानों में चोरी करने वाले दो बदमाश दबोचे

जयपुर। खोराबीसल पुलिस ने मंदिर और सूने मकानों में चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 शक्ति आरोपियों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शनि मंदिर से चोरी किए गए चांदी के तीन छत्र तथा एक मकान से चोरी की गई पानी की मोटर बरामद की है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि 25 जुलाई को नांगल जैसा बोहरा स्थित शनि मंदिर (देव तलाई) से चांदी के छत्र चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच के दौरान घटनास्थल और बैनाड रोड के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनके आधार पर राकेश प्रजापत (21) निवासी झामदा कला (चाकस), हाल निवासी कश्चनी की पहचान हुई। आरोपी पहले से कश्चनी थाना क्षेत्र के चोरी के मामले में जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पुनर्ताछ की, जिसमें उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी किए गए तीनों चांदी के छत्र बरामद कर लिए गए। आरोपी को खिलाफ पहले भी चोरी और नकबजनी के मामले दर्ज है। वहीं दूसरे मामले में 20 जुलाई को ग्रीन पार्क, नांगल जैसा बोहरा निवासी राकेश कुमार ने चोरी के आधार, लाइट का सामान और करीब 10 हजार रुपये की पानी की मोटर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबि की सूचना के आधार पर सुनील लोरा (26) निवासी नारायण नगर, दादी का फाटक (शोटवाडा) को भेरूजी मंदिर के पास से गिरफ्तार किया।

पुलिस ने शुरु किया ‘‘ऑपरेशन चौकस’’

जयपुर। राजधानी के पश्चिम जिले में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जयपुर पश्चिम पुलिस ने ऑपरेशन चौकस अभियान शुरू किया है।

‘‘आपकी सूचना, हमारी कार्रवाई’’ थीम पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत आमजन से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 7300012212 व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ने बताया कि इस नंबर की सीधी निगरानी डीसीपी कार्यालय करेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति को पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी तथा प्राप्त प्रत्येक सूचना का सत्यापन कर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से नशे और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री, अवैध हथियारों के निर्माण और खरीद-फरोख्त, जुआ-सट्टा तथा गुंडागर्दी एवं अन्य असाामाजिक गतिविधियों की सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर देने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि आमजन की सक्रिय भागीदारी से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा और समाज को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

तेज रफ्तार एस.यू.वी. ने स्कूटी सवार छात्र को रौंदा

पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र में वंदेमातरम मार्ग पर हुआ हादसा, चालाक फरार

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र के वंदेमातरम मार्ग पर बारिश के दौरान तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से स्कूटी सवार 19 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद एसयूवी डिवाइडर से टकरा गई और उसका टायर फटने पर चालक कुछ दूरी पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो गुरुवार को सामने आया।

थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पहचान विकल्प उर्फ राजा मीणा (19) निवासी सूर्य नगर, गोपावपुरा बाईपास रूट में हुई है। जो बारिश के दौरान स्कूटी से जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से आई एसयूवी ने उसे सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी धीषण थी कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद एसयूवी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसका

अगस्त तक 1200 पेयजल योजनाओं का होगा जल अर्पण, 2500 गांव होंगे लाभान्वित

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल जीवनमिशन की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन तथा जल अर्पण दिवस के आयोजन को

‘हर जिले में ड्रग से जुड़े 1 0 प्रमुख केस और 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं की होगी सूची तैयार, सम्पत्ति होगी जब्त’

मुख्य सचिव ने प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में नार्को समन्वय केंद्र तंत्र (एनसीओआरडी) की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को सख्त एवं समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी पुलिस थानों में मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ड्रग्स की जब्त और तस्करो के विरुद्ध अभियान की और अधिक तेज किया जाए। साथ ही, जब्त ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों को प्रदेश के सभी पुलिस थानों मे एक दिन एक साथ विशेष अभियान चला कर नष्ट किया जाए।

उन्होंने कहा कि आदतन अपराधियों के विरुद्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित मजबूत चार्जशीट



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में नार्को समन्वय केंद्र तंत्र की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई।

तैयार की जाए, जिससे न्यायालय में प्रभावी पैरवी हो सके और दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाई जा सके। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को केन्द्र सरकार की ‘डिटेक्ट-डिसरप्ट-डैस्ट्रॉय’ नीति के आधार पर ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क को समाप्त

करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए योजनाबद्ध एवं समन्वित कार्रवाई की जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक ड्रग्स से जुड़े 10 प्रमुख मामलों की सूची तैयार करें

तथा उनमें से 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में वर्ष 2026-29 के लिए मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य

प्राकृतिक खेती में राजस्थान बना मिसाल : क्लस्टर गठन में दूसरा, कृषक पंजीकरण में तीसरा स्थान

राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का दिख रहा प्रभावी असर

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार ढाई लाख किसानों को जोड़कर एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत राज्य में अब तक 2 हजार 380 क्लस्टर गठित किए जा चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश के बाद देशभर में सर्वाधिक है। इन क्लस्टरों से प्रदेश के 2 लाख 12 हजार 346 किसान जुड़े हैं, यह संख्या आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक है। साथ ही, अब तक राज्य के लगभग 91 हजार 166 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाई जा चुकी है, जो राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करती है। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक लगभग 49 करोड़ 97 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को नई दिशा देने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। प्रदेश में 50 हजार

- 2 लाख से अधिक किसान कर रहे हैं 91 हजार हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती**
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से मिल रहा उत्तम प्रशिक्षण-उन्नत विपणन**
- मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी, किसानों का उत्पादन बढ़ा, लागत घटी**

किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक किसानों के माध्यम से जैविक खाद उत्पादन के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किया जा रहे हैं, जिससे किसानों को जैविक उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

राज्य सरकार पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बेलों से खेती करने वाले किसानों को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 हजार 856 करोड़ रुपये का अनुदान मिशन की गोशालाओं को दिया गया है। बजट 2025-26 में कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में सेंट ऑफ क्वालिटीस फॉर नैचुरल फार्मिंग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 25 नवंबर 2024 को प्रारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा किसानों की आय बढ़ाना है। यह मिशन केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रमाणन और विपणन की समग्र सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इसके तहत देशभर में 527 कृषि विश्वविद्यालय, 194 स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थान तथा 18 उ्कृष्टता केंद्र मिशन अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दो वर्षों तक उपलब्ध करवाई जा रही है। नीति आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक

खेती अपनाने वाले लगभग 91 प्रतिशत किसानों के उत्पादन में वृद्धि हुई तथा लगभग 90 प्रतिशत किसानों की उत्पादन लागत में कमी आई है। साथ ही, मिट्टी के स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है।

प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि और भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ कृषि व्यवस्था का आधार बन रही है। यह समृद्ध किसान, स्वस्थ समाज और सुरक्षित पर्यावरण की आधारशिला है। जब किसान प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर खेती करेगा, तभी विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को नई गति मिलेगी।प्राकृतिक कृषि ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें प्रकृति के अनुरूप खेती की जाती है तथा मिट्टी, जल, जैव विविधता और सूक्ष्मजीवों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें स्थानीय संसाधनों, विशेषकर देशी गाय आधारित जैविक घोल, फसल अवशेष, मल्लिचंग तथा मिश्रित खेती का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम होने से किसानों की उत्पादन लागत में कमी आती है और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध होते हैं।

कानून व्यवस्था कि बिगड़ी स्थिति का जिम्मेदार कौन, किसकी है जवाबदेही? : नेता प्रतिपक्ष

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने प्रदेश में लगातार कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भावपा सरकार, आम जनता को यह विश्वास दिलाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है कि वह अपराध नियंत्रण पर गंभीर है। प्रदेश में लगातार आपराधिक वारदातें हो रही है और बेरोषि अपराधी

खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।जुली ने कहा कि राजस्थान में लगातार आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं, अपराधी बेरोषि होकर अपराध कर रहे हैं। प्रकृति का एक मामूली विवाद में मानसरोवर इलाके में चार गुंडों ने एक युवक की पीट-पीट कर जान ले ली। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री तीनों ही जयपुर से विधायक हैं,

उसके बावजूद राजधानी में कानून-व्यवस्था का यह हाल है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों में इतना दुसाहस कैसे हो रहा है? सरेशा किसी की जान कैसे ली जा सकती है? अभी कुछ दिन पहले ही इसी घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक नाइट क्लब में रात के 3 बजे सरेआम पार्टी चल

रही थी, जहाँ एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। शर्मनाक बात तो यह है कि उस पार्टी में भरतपुर से फरार चल रहे शक्ति कैदी भी मौजूद थे। क्या यह जयपुर की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर बड़ज़ सवाल नहीं है?नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजधानी ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में ही हालात बेहद खराब हैं।

प्रारंभिक जांच के आधार पर 1.39 करोड़ रुपये से अधिक का सौंदर्य इनपुट टैक्स क्रेडिट चिह्नित किया गया है। साथ ही, फर्म के क्रेडिट लेजर में 27.47 लाख रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्तमान में उपलब्ध पाया गया है।

रंगाई-छपाई से जुड़े लोगों ने सीईटीपी पर उठाए सवाल

जयपुर। सांगानेर क्षेत्र के शिकारपुरा रोड, गवार-बागमिया में प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में रंगाई-छपाई उद्योग से जुड़े फैक्ट्री संचालकों और मजदूरों ने गुरुवार को संयुक्त रूप से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना पर्याप्त समय और उचित व्यवस्था उपलब्ध कराए फैक्ट्रियों को सीज किया जा रहा है तथा बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे हजारों मजदूरों और उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ब हो गया है। साथ ही भूख मरने की नीबत आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सांगानेर रंगाई-छपाई क्षेत्र का कॉमन एम्प्लुएड ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) लंबे समय से पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो रहा है। प्लांट या तो बंद पड़ा रहता है अथवा वर्तमान में केवल 1 एम्पलुडी क्षमता पर संचालित किया जा रहा है, जबकि क्षेत्र की आवश्यकता इससे कई अधिक है। फैक्ट्री संचालकों ने बताया कि सीईटीपी में 800 सदस्य हैं, जिन्होंने सदस्य बनने के लिए 15 से 20 लाख रुपये तक का योगदान दिया है।

16 अगस्त तक बड़ी खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि

जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है। इससे अब हजारों ऐसे किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाए थे। योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी एवं बटाईदार किसान अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय को सुरक्षित बनाने, खेती में जोखिम कम करने तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत किसानों को सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, जलभराव सहित अन्य अतिसूचित प्राकृतिक जोखिमों से फसल क्षित होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने योजना के सफल संचालन हेतु चार बीमा कंपनियों का चयन किया है, जो विभिन्न जिलों में किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराएंगी। किसान 16 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, निकटतम बैंक, सहकारी समिति,

राज ममता कार्यक्रम के तहत वेब एप बनेगा मानसिक स्वास्थ्य में सहायक

जयपुर। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खोंवसर ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के तहत अवचंद्र चिंता और आत्महत्या आदि की रोकथाम के लिए राज ममता कार्यक्रम चलाए जाने की की गई बजट घोषणा की गई थी, इसी कड़ी में प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ एवं साक्ष्य-आधारित बनाने की दिशा में चिकित्सा विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठीइ ने बताया कि राज ममता कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जयपुर, जोधपुर मेंडिंकल कॉलेज और एम्स जोधपुर में वेब आधारित टूल किट ग्लोबल मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल लागू किया जाएगा। यह वेब-आधारित डिजिटल

एप मरीजों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर एवं वैज्ञानिक पहचान सुनिश्चित करेगा, जिससे उपचार में तेजी आएगी और विशेषज्ञ सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मेनचेस्टर के सहयोग से उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। राठीइ ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक वेब-आधारित डिजिटल असेसमेंट टूल है, जिसके माध्यम से मरीज का निर्धारित प्रश्नों के आधार पर साक्षात्कार किया जाएगा। साक्षात्कार पूरा होते ही सिस्टम स्वतः रिपोर्ट तैयार करेगा।

सार-समाचार

पशु चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण

जयपुर। पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीना के निर्देश पर विभागीय अधिकारी इन दिनों पशु चिकित्सा संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। गुरुवार को विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. संजय कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय एक दल ने जयपुर जिले की तीन पंचायत समितियों के सात पशु चिकित्सा संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पशु चिकित्सालयों एवं उपकेंद्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवा भंडारण, स्वच्छता व्यवस्था, उपकरणों की उपलब्धता, अभिलेखांश प्रणाली तथा पशुपालकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण दल ने संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित उपस्थिति, उपचार व्यवस्था तथा पशुपालकों से बेहतर संवाद बनाए रखने के संबंध में चर्चा की। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। डॉ। संजय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिन संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पाई गई, वहां संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधातात्मक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि कुछ संस्थानों में कर्मचारी बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए उनके खिलाफ आपराधनात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, जिन संस्थाओं में अनियमितता पाई गई है वहां भी संबंधित कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। दल ने जिन संस्थानों का निरीक्षण किया उनमें चाकस पंचायत समिति के बाडा पदमपुरा का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा उपकेंद्र बापूगांव, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कोखावदा, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय फागी, तथा पंचायत समिति माधोराजपुरा के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय कादेडा और पशु चिकित्सा उपकेंद्र डाबीच शामिल हैं।

तीन विधानसभा कार्मिक सेवानिवृत्त

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को विधानसभा के तीन कर्मियों सहायक लेखाधिकारी नरसी राम गुर्जर, सहायक कर्मचारी आनन्द व्यास और राजकुमार पंवार को सेवानिवृत्ति पर साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी। देवनानी ने कहा कि विधान सभा में सभी के प्रति समभाव है। उन्होंने कहा कि उनके स्पीकर पद के कार्यकाल में विधान सभा कर्मियों का यह 25 वर्ष सेवानिवृत्ति समारोह है। वे सभी समारोह में व्यक्तिः मौजूद रहे। इन समारोह की सुखद अनुभूति यह है कि यहां सहायक कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक का सेवानिवृत्ति समारोह एक जैसा आयोजित किया जाता है और विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी इन समारोह में मौजूद रहते हैं। इस मौके पर राजस्थान विधान सभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के. के. शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव संजीव शर्मा, वित्तीय सलाहकार अमूर्त जोशी और राजस्थान विधान सभा कर्मचारी सहकारी साहा समिति के अध्यक्ष रवि जैन सहित विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। समारोह का संचालन दुर्गादास मूलचंदानी ने किया।

मुरली मनोहर अर्किचन महाराज का सम्मान

जयपुर। छोटी काशी के प्रख्यात कथावाचक मुरली मनोहर अर्किचन महाराज को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत कृष्ण नगर द्वितीय, लालकोठी में आयोजित सम्मान समारोह में जय श्रीनारायण परिवार की ओर से वंदा गुरुदेव श्री श्यामसुंदर आचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान इन्द्र मण्जिजी महाराज ने प्रदान किया। समारोह में आदित्य वर्धन, गिरधर शर्मा सहित अनेक श्रद्धालु एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। सम्मान पत्र का वाचन करते हुए कहा गया कि महाराज ने ‘‘पीबत भागवत रसमालावर्ण’’ की भावना को साकार करते हुए देशभर में लगभग 5०0 भाववत कथाओं के माध्यम से जनमानस में आध्यात्मिक चेतना का संसार किया है। उनकी ओजस्वी वाणी, सरल एवं प्रभावशाली शैली, सूक्ष्म विश्लेषण तथा गूढ़ आध्यात्मिक विषयों के प्रभावशाली में प्रस्तुत करने की कला ने उन्हें देश के लोकप्रिय कथावाचकों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित किया है।

‘पृथ्वीराज नगर में हाईटेंशन लाइन के नीचे पिछले 1० वर्षों में 8०० घर बने कैसे?’

हाईकोर्ट ने 12 अगस्त की अगली सुनवाई पर जेडीए के ज़ोन18-19 में गत दस वर्षों में पदास्थापित रहे प्रवर्तन अधिकारियों की सूची और उनके मौजूदा पद का ब्यौरा मांगा

–यादवेंद्र शर्मा–

जयपुर, 3० जुलाई। राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर में हाईटेंशन लाइन के नीचे 800 से ज्यादा घर और 200 दुकानें बने होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने जेडीए के अधिवक्ता को कहा है कि जेडीए के पीआरएन ज़ोन 18 व 19 में बोते 1० साल में तैनात हुए अफसरों का विवरण और उनके मौजूदा पदस्थापन की जगह भी बताए।

इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह 12 अगस्त तक शपथ पत्र पेश कर प्रवर्तन अधिकारी का बयान सत्यापित करें कि यहां हाईटेंशन लाइनों के नीचे बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो गए हैं। एक्टिंग सीजे एस.पी. शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश साहेब सिंह

- जेडीए की ओर से अदालत में कहा गया कि, अगली सुनवाई पर अधिकारियों की जानकारी के साथ इन अतिक्रमणों की फोटो सहित जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करेंगे।

- जेडीए प्रशासन ने माना कि अजमेर रोड से वंदे मातरम् रोड तक करीब डेढ़ किमी. क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन कॉरिडोर में 800 मकान व 200 दुकानें बनी हुई हैं, इनमें से 206 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है।

की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। साहेब सिंह की ओर से अदालत में अधिवक्ता रामरख शर्मा पेश हुए थे।

सुनवाई के दौरान जेडीए के स्थानीय प्रवर्तन अधिकारी गंगाराम अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने गत 24 अप्रैल को ही कार्यभार संभाला है। जबकि पृथ्वीराज नगर क्षेत्र

में हाईटेंशन लाइनों के आसपास और उसके नीचे करीब 8०0 मकान और 200 दुकानें बनी हुए हैं। जेडीए के ज़ोन उपायुक्त की ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि यहां अधिकांश निर्माण 1० साल से भी अधिक पुराने हैं। जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत को बताया कि करीब 2०6

लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया जा चुका है। इसके साथ-साथ मौके पर हुए नए अतिक्रमणों को तत्काल प्रभाव से हटایा जा रहा है। अजमेर रोड से वंदे मातरम् रोड तक करीब डेढ़ किमी एचटी लाइन कॉरिडोर में कराए सर्वे में करीब 8०0 मकान व 2०0 दुकान प्रभावित पाई गई हैं। मौजूदा प्रवर्तन अधिकारी के कार्यकाल में कोई बड़ा नया अतिक्रमण नहीं हुआ है।

इस पर अदालत ने 1० साल में यहां तैनात प्रवर्तन अधिकारियों की विस्तृत जानकारी मांगते हुए जेडीए को मौजूदा हालात की रिपोर्ट देने को कहा है। जनहित याचिका में अधिवक्ता रामरख शर्मा ने बताया कि दोनों ज़ोन में हाईटेंशन लाइन के दोनों ओर 6० फीट की सेक्टर रोड है। कई लोगों ने यहां 3० फीट तक अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की।

दिल्ली सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आंखों समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

याचिका में कहा गया है कि पैलेट गन को भले ही कम घातक हथियार बताया जाता हो, लेकिन इससे बड़ी संख्या में घातु के छरें निकलते हैं। इससे आंखों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान का खतरा रहता है। पैलेट गन का इस्तेमाल संविधान के तहत न्यायसंगत बल प्रयोग की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

आठ जिलों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उल्लेखनीय है कि लोक अदालतें विवादों के त्वरित और किफायती समाधान की व्यवस्था हैं। इसमें आपसी सहमति से निर्णय किए जाते हैं, जिससे आमजन के समय और धन दोनों की बचत होती है।

एक तरफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की शिकायत भी नहीं करती। इन टिप्पणियों के बाद भारी आक्रोश फैल गया। केरल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरएसएस ने आधिकारिक तौर पर इस बयान से खुद को अलग करते हुए कहा कि ये मोहनदास के निजी विचार हैं तथा संघ ने उनकी निंदा की।

वहीं भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर जेन जेड प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए उन्हें “जनरेशन गट” कहा। उन्होंने उनके वीडियो को “उल्टी आने लायक” और “बदसूती से भरा हुआ” बताया तथा उनकी तुलना दंगगी फैलाने वाले तिलचट्टों से करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए।

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

दीपके ने गृह मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इससे पहले अभिजीत दीपके ने कहा कि जिस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला किया गया और उनका खून बहाया गया, वह गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बिना संभव नहीं था।

दीपके की यह मांग कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शाह पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग करने के एक दिन बाद आई। दीपके ने कहा कि वह राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, “मैं भी मानता हूं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए।”

सीजेपी को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों को खारिज करते हुए दीपके ने कहा, “यदि गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथ में होने के बावजूद हमें विदेशी फंड मिल रहा है, तो यह भी उनकी विफलता है। फिर आप किस तरह के चाणक्य हैं? ऐसी स्थिति में भी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।”

दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए पत्थरबाजी की पूरी घटना की साजिश रची। उनका दावा था कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल पर पुलिस एक ट्रक भरकर पत्थर और एक क्षतिग्रस्त वाहन लेकर आई, ताकि यह दिखाया जा सके कि पुलिस की कार्रवाई

हिंसा के जवाब में की गई।

उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस ने ही पत्थरबाजी करवाई। भाजपा के गुंडे आए, उन्होंने पत्थर फेंके और इसका दोष छात्रों पर मढ़ दिया गया।”

दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने उन्हें और उनके परिवार को पार्टी में शामिल होने के लिए धमकाया। उन्होंने कहा, “मुझे धमकी दी गई। मेरे माता-पिता को धमकी दी गई है कि वे मुझे भी भाजपा में शामिल होने के लिए राजी करें। हमें कहा गया कि या तो पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो।” वहीं, भाजपा नेता केशव उपाध्ये ने दीपके पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि उन्हें राहुल गांधी की लाइन पर चलना है तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “वे एक आंदोलन का चेहरा था। भाजपा सरकार ने उनकी मांगें मानते हुए पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मन् प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया। उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वे राजनीति कर रहे हैं। यदि उन्हें राहुल गांधी की लाइन पर चलना है तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए।”

भाजपा ने दीपके और उनके परिवार को धमकी दिए जाने के सभी आरोपों से इनकार किया।

सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी तीन प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शामिल होंगे

इसकी शुरुआत होगी किर्गिस्तान में होने जा रहे एससीओ समिट से, जिसमें शामिल होने प्र.मंत्री मोदी किर्गिस्तान जाएंगे

–जाल खंबाता–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 3० जुलाई। भारत 2०26 के सबसे व्यस्त कूटनीतिक चरणों में से एक की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सिर्फ एक महीने में तीन बड़े-बड़े मल्टीलेटरल कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री मोदी तीन दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर भी जाएंगे। इस दौरान वे द्विपक्षीय बैठकों और भारतीय समुदाय के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें “मैलबर्न मोट्स मोदी” कार्यक्रम भी शामिल है।

भारत 2०26 के सबसे व्यस्त कूटनीतिक चरणों में से एक का गवाह बनने जा रहा है। सितंबर महीने की शुरुआत किर्गिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में पी.एम. मोदी की मौजूदगी से होगी।

इसके बाद, नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत

- एससीओ (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन) में चीन, रूस, भारत, ईरान, बेलारूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

- एससीओ समिट के बाद दिल्ली में ब्रिक्स समिट का आयोजन होगा, उसके बाद प्र.मंत्री मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे, जहाँ वे यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली को संबोधित करेंगे।

करेगा। इसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में भी संबोधित करेंगे। यह व्यस्त कार्यक्रम दिखाता है कि अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच, नई दिल्ली अपने अंतरराष्ट्रीय संपर्क और कूटनीतिक पहुंच को सक्रिय रूप से मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।

यह व्यस्त कूटनीतिक कार्यक्रम 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन से

वंदे मातरम् विधेयक लोकसभा से भी पारित

नई दिल्ली, 3० जुलाई। लोकसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2०26 को शोर-शराबे के बीच गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक एक दिन पहले ही राज्यसभा से पारित हुआ था। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण और सम्मान प्रदान करना है।

सरकार का कहना है कि यह विधेयक भारत की सांस्कृतिक विरासत,

- यह विधेयक ‘वंदे मातरम्’ को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाओं को सशक्त करेगा। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद विधेयक पारित कर दिया गया और कार्रवाईही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राय ने कहा कि यह केवल विधायी संशोधन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता है।

‘बिना ‘‘लोगो’’ व विज्ञापन वाले कैरीबैग का भुगतान वसूल सकते हैं दुकानदार’

राज्य उपभोक्ता आयोग ने डी-मार्ट रेवन्यू मार्केट लि. बनाम शेखर कुमार स्वर्णकार व कपिल देव सोनी के खिलाफ दायर 2 अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए

–यादवेंद्र शर्मा–

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने फैसला दिया है कि दुकानदार, उपभोक्ताओं से कानूनी तौर पर उन “कैरीबैग” का भुगतान ले सकता है, जिन पर कोई विज्ञापन अथवा किसी कंपनी का “लोगो” नहीं छपा हुआ हो।

उपभोक्ता आयोग ने यह फैसला डी-मार्ट रेवन्यू मार्केट लि. बनाम शेखर कुमार स्वर्णकार व कपिल देव सोनी के खिलाफ दायर 2 अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया। इस मामले में डी मार्ट की ओर से अधिवक्ता हेमांग कुमावत पैरवी के लिए पेश हुए थे। यह फैसला आयोग की न्यायाधीश उर्मिला वर्मा व करूणा जैन की पीठ ने सुनाया है।

इस मामले के तथ्यों के अनुसार, शेखर कुमार स्वर्णकार ने 862 रुपए का

रामगढ़ बाँध के बहाव क्षेत्र के सभी एनीकट हटाएं- हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बहाव क्षेत्र में एक भी सबमर्सिबल पंप नहीं होना चाहिए

जयपुर, 3० जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को बांध के बहाव क्षेत्र में मौजूद सभी एनीकटों को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, अदालत ने कहा कि क्षेत्र में सबमर्सिबल पंप भी नहीं होने चाहिए। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश रामगढ़ बांध सहित, प्रदेश के अन्य जल स्रोतों में अतिक्रमण से जुड़े मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिए।

अदालत ने कहा कि बांध और उसमें पानी लाने वाली नदियों को मूल स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाए। अदालत ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि बांध के कैचमेंट एरिया में किन लोगों ने अतिक्रमण किया है और इन्हें हटाने के लिए क्या किया गया। अदालत ने कैचमेंट एरिया की जमीन और यहां बने फार्म हाउस व होटलों का ब्यौरा भी मांगा है। खंडपीठ ने जयपुर व कोटपूतली

- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करके यह बताने को कहा है कि कैचमेंट एरिया में किन लोगों ने अतिक्रमण किए हैं। अदालत ने कैचमेंट एरिया की जमीन और वहाँ बने फार्म हाउस व होटलों का ब्यौरा भी मांगा।

कलेक्टर को 13 अगस्त की रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि रामगढ़ बांध में पानी लाने वाली नदियों में पानी बयों नहीं आ पा रहा।

अदालती आदेश के पालन में जयपुर कलेक्टर वीसी के जरिए उपस्थित हुए। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में आमेर एसडीओ का शपथ पत्र पेश किया और बताया कि कुल 625 रेफरेंस थे, जिनमें से 4०4 निस्तारित हो चुके हैं और बाकी लंबित चल रहे हैं। जिन केंसों की निस्तारण हो चुका है, उनकी जमीन भी राज्य सरकार में दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा, बांध मामले में दो कमेटीयां बनी हुई हैं। एक कमेटी

की 14 व दूसरी की 17 मीटिंग हो चुकी है। इस पर खंडपीठ ने एजी से कहा कि वे शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में आगामी सुनवाई पर राज्य सरकार एक विस्तृत शपथ पत्र पेश कर बताए कि कितने अतिक्रमण हटाए थे और वे किसके थे। इस दौरान न्याय मित्र डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि रामगढ़ बांध में पानी लाने का मुख्य जरिया बाणगांग नदी है, जो विराटनगर, शाहपुर व अन्य जगहों से होती हुई बांध में पानी लाती है। इसके बहाव क्षेत्र में कई फार्म हाउस, रिसोर्ट व होटल बन गए हैं और बहाव क्षेत्र में बने एनीकटों के पीछे भी मिट्टी जमा हो गई है, जिससे पानी का बहाव क्षेत्र में फ्लो नहीं रहता।